बाज़ार आधारित आर्थिक प्रेषण (MBED) चरण 1

प्रिलिम्स के लिये:

डे-फॉरवर्ड मार्केट, बाज़ार आधारित आर्थिक प्रेषण

मेन्स के लिये:

विद्युत क्षेत्र के लिये साइबर सुरक्षा दिशा-निर्देश, एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक आवृत्ति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **विद्युत मंत्रालय** ने **उपभोक्ताओं की बिजली खरीद लागत** को 5% तक कम करने के लिये **बाज़ार आधारित आर्थिक प्रेषण (Market Based Economic Despatch- MBED)** चरण 1 के कार्यान्वयन के लिये फ्रेमवर्क जारी किया।

- यह बिजली बाज़ार के संचालन में सुधार और **"एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक आवृत्ति, एक मूल्य"** ढाँचे की ओर बढ़ने में महत्त्वपूर्ण कदम है। इसका **कार्यान्वयन 1 अप्रैल, 2022** से शुरू करने की योजना है।
- इससे पहले सरकार ने विद्युत क्षेत्र के लिये साइबर सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी किये थे।

प्रमुख बिंदु

- **परिचय:**
  - **सभी राज्यों की बिजली की मांग** को इष्टतम मूल्य पर **बिजली आवंटित करने वाले केंद्रीय पूल** के माध्यम से पूरा करने का प्रस्ताव है।
    - वर्तमान में विद्युत वितरण कंपनियाँ (डिस्कॉम) राज्यों के भीतर उपलब्ध स्रोतों से बिजली का वितरण कर रही हैं, जो हमेशा उच्च ऊर्जा लागत के साथ समाप्त होती है।
  - MBED यह सुनिश्चित करेगा कि देश भर में सबसे सस्ते उत्पादन के संसाधनों को समग्र प्रणाली की मांग को पूरा करने के लिये उपयोग किया जाए।
  - इस प्रकार यह व्यवस्था **वितरण कंपनियों** और **बिजली उत्पादकों दोनों के लिये ही एक सफल प्रयास** होगा और अंततः इससे बिजली उपभोक्ताओं को महत्त्वपूर्ण वार्षिक बचत भी होगी।
  - MBED का लक्ष्य **एक समान मूल्य निर्धारण ढाँचा स्थापित** करना है जो अधिक खर्चीले उपकरणों को कम करते हुए सस्ते लागत और सबसे कुशल जनरेटर को प्राथमिकता देता है, जो राष्ट्रीय क्षमता में क्रमबद्ध रूप से सुधार सुनिश्चित करेगा।
  - यह **राष्ट्रीय विद्युत नीति (NEP) 2021 के मसौदे के अनुरूप** है, जिसका उद्देश्य 2023-2024 तक अल्पकालिक बिजली बाज़ारों की पहुँच को दोगुने से अधिक करना है।
- **एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक आवृत्ति:**
  - भारत के पास अपने जटिल इंटरकनेक्टेड पावर ग्रिड के माध्यम से एक महत्त्वपूर्ण अंतर-क्षेत्रीय विद्युत पारेषण क्षमता है जिसके लिये केंद्र, राज्यों और निजी क्षेत्र द्वारा संचालित कोयला, गैस, हाइड्रो, परमाणु व हरित ऊर्जा स्रोतों में ग्रिड ऑपरेटरों एवं बिजली परियोजना जनरेटर के बीच घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता होती है।
  - पिछले दशक में महत्त्वपूर्ण निवेश के साथ भारतीय बिजली प्रणाली ने बिजली क्षेत्र में बड़े अंतर-क्षेत्रीय हस्तांतरण किये हैं और **"एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक आवृत्ति (One Nation, One Grid, One Frequency)"** के रूप में अपनी स्थिति का आकलन कर अधिकांश बाधाओं को समाप्त कर दिया है।
  - यह राज्य के स्वामित्व वाली पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (Power System Operation Corporation Limited-POSOCO) है, जो इन जटिल कार्यों का प्रबंधन राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (National Load Despatch Centre- NLDC), क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (Regional Load Despatch Centres- RLDC) और राज्य भार प्रेषण केंद्र (State Load Despatch Centres- SLDC) के माध्यम से करती है।
    - देश में 33 SLDC, पाँच RLDC (राष्ट्रीय ग्रिड बनाने वाले पाँच क्षेत्रीय ग्रिड के लिये) और एक NLDC है।
  - इस सक्षमता के बावजूद देश में मौजूदा बिजली निर्धारण और प्रेषण तंत्र की स्थिति निष्क्रिय बनी हुई है तथा दिन-प्रतिदिन की

प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप देश के उत्पादन संसाधनों का उपानुकूलतम उपयोग होता है।

- डे-फॉरवर्ड मार्केट (Day-Ahead Market) एक वित्तीय बाज़ार है जहाँ बाज़ार सहभागियों ने अगले दिन के लिये वित्तीय रूप से बाध्यकारी डे-फॉरवर्ड कीमतों पर विद्युत ऊर्जा की खरीद और बिक्री की है।

स्रोत: पीआईबी

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/market-based-economic-despatch-phase-1